

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)
के रे बो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट,
मडिवाला, बेंगलूरु - 560 068



CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles - Govt. Of India)
CSB Complex, BTM Layout
Madivala, Bengaluru - 560 068

No.CSB-29(Int.)/GPF/2011-12

Date: 2nd August 2018

CIRCULAR

Sub: GPF interest w.e.f 01.07.2018 to 30.09.2018 – regarding

Please find enclosed herewith the GOI Resolution F.No.5(1)-B(PD)/2018, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) dated: 17th July 2018 wherein the GPF interest at the rate of 7.6% (*seven point six per cent*) had been fixed w.e.f. 1st July 2018 to 30th September 2018 which is self-explanatory, for kind information.

[CA MANOHARAN A]
JOINT DIRECTOR [FINANCE]

To:

All the Delegated Units



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD



(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)

केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला

CSB Complex, BTM Layout, Madiwala

बेंगलूरु Bengaluru- 560 068

सं.केरेबो-29(ब्याज)/साभनि/2011-12

दिनांक : 02.08.2018

परिपत्र

विषय : दिनांक 01.07.2018 से 30.09.2018 तक के सामान्य भविष्य निधि ब्याज के संबंध में ।

कृपया भारत सरकार संकल्प एफ.5[1]-बी[पीडी]/2018, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग [बजट प्रभाग] दिनांक 17 जुलाई, 2018 जिसमें 01 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि ब्याज 7.6% [सात दशमलव छः प्रतिशत] निर्धारित किया गया, स्वतः स्पष्ट और सूचनार्थ संलग्न है।

अ. मनोहरन

[सीए मनोहरन ए.]

संयुक्त निदेशक [वित्त]

सेवा में

सभी प्रत्यायोजित इकाइयाँ

(PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.No. 5(1)-B(PD)/2018
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

New Delhi, the 17th July, 2018

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2018-2019, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.6% (Seven point six percent) w.e.f. 1st July, 2018 to 30th September, 2018. This rate will be in force w.e.f. 1st July, 2018. The funds concerned are:

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.


(Anjana Vashishtha)
Deputy Secretary (Budget)

To,
The Manager, (Technical Branch)
Government of India Press, Mayapuri, Delhi.

F.No.5(1)-B(PD)/2018

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog

Copy also forwarded to :-

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division)
5. Financial Adviser of Ministries/Departments (8 copies)
6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
7. Controller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
9. Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
12. NIC - For uploading on webhost


(A.S. Chowdhury)
Under Secretary (Budget)

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनाथ)
एफ. नं. 5(1)-बी(पी.डी.)/2018
मंत्रालय सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई, 2018

आम जनकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2018-2019 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा राशियों पर ही जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक 7.6% (सात दशमक 6 प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी, संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य सेवा भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुष्म विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुष्म कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गौरी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. राजस्व सेवा कर्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प मंत्रालय में प्रकाशित किया जाए।


CENTRAL SILK BOARD
Bansal/Banalore-560 068
27 JUL 2018
स/नं. 4278
प्राप्त/Disposed on

सेवा में,
प्रबंधक (तकनीकी शाखा)
भारत सरकार मद्रासालय
मायापुरी, दिल्ली।

फा. संख्या 5(1)-बी(पी.डी.)/2018

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संविमतल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित।

निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणधीन सभी कार्यालय
2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)।
4. कार्मिक, लोक शिक्षणत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
5. मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सहायकार (6 प्रतियां)।
6. मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
7. रक्षा सेवा भविष्य निधि।
8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
9. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-सचिव।
10. सचिव स्टाफ एस, राष्ट्रीय उद्योग परिषद।
11. सभी सदस्य स्टाफ एस, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
12. एनआईसी वेबसाइट हेतु।


अनिल कुमार
(अरुण श्याम चौधरी)
आर सचिव (बजट)